

पहले मुख्य समाचार।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। गठन की तिथि से अट्ठारह महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा नया वेतन आयोग।
- प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान प्रारम्भ। चार नवम्बर से शुरू होगी गणना प्रक्रिया, सात फरवरी दो हजार छब्बीस को होगा अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
- प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिये दस प्रमुख अधिनियमों में व्यापक संशोधन। सजा का प्रावधान समाप्त। अब सिर्फ आर्थिक दण्ड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था।
- चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण बदला प्रदेश के मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट के बीच आज भी बेमौसम बारिश की आशंका।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री आश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे।

एट्थ-पे कमीशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अब करीब-करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग किया है। 18 मंथ के अंदर यह रिपोर्ट आएगी इसकी एट्थ-पे कमीशन जस्टीस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयर परसन बनाया गया है। अशकुल घोष एंड पंकज जैन हू इज द सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे विल बि द मेम्बरर्स।

सरकार ने इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच तथा सिफारिश करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी।

इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दे दी है। इस सम्बन्ध में सूचना एवं प्रसारण मंत्री आश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 के लिए लगभग 37 हजार नौ सौ 52 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर के अभियान की कल शुरुआत हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार एसआईआर के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के 1 लाख 62 हजार 486 बूथों पर एक साथ यह पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। गणना प्रपत्रों की छपाई और बीएलओ का प्रशिक्षण कल से शुरू हो गया है। गणना प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी, मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है।

एक दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसे में एक संवैधानिक संस्था के रूप में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है।

स्पेशल इंटरसिव रिव्यू का जहां तक सवाल है, यह एक जरूरी औपचारिकता है कि हर राज्य के अंदर जो मतदाता इलेक्टोरल रोल है, उसका रिवीजन हो और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। जो मतदाता मृतक हो चुके हैं या जिन मतदाताओं के नाम का डुप्लिकेशन है, उसे हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है।

प्रदेश सरकार ने कल आईएस संवर्ग के छियालीस और पीसीएस संवर्ग के सत्ताइस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें विन्ध्याचल, सहारनपुर और मेरठ मण्डल के मण्डलायुक्त और हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशाम्बी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती तथा रामपुर के जिलाधिकारियों का भी तबादला शामिल है।

प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिये दस प्रमुख अधिनियमों में अधिकांश आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिये हैं। नई व्यवस्था में सजा का प्रावधान समाप्त कर सिर्फ आर्थिक दण्ड और प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार-प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश दो हजार पचीस को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या महायोजना दो हजार इक्तीस से सम्बन्धित प्रस्तावों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता तीनों का समन्वित रूप होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या का विकास न केवल धार्मिक पर्यटन बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी प्रेरक उदाहरण बनें। मुख्यमंत्री ने कहा अयोध्या केवल शहर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि अयोध्या विकास क्षेत्र में एक सौ उन्सठ निवेश परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें आठ हजार पांच सौ चौरानबे करोड़ रुपये का निवेश होने की सम्भावना है।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना प्रस्तावित है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि श्रीराम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का संदेश भी देगा। उन्होंने कहा कि ध्वज का भार करीब 11 किलो होगा ऐसे में उसे फहराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है।

जो पताका लहराया जाना है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एक ऊंचाई पर जाएगा कोई 11 फीट का है और 22 फीट की चौड़ाई इस प्रकार का पताका है तो कल सेना के लोग आए थे और उन्होंने रिहर्सल किया हम उनकी राय को पूरा-पूरा क्रियान्वित करेंगे।

छठ महापर्व के सम्पन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों, बिहार और झारखण्ड से अन्य प्रदेशों को वापस जाने वाले यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा सुगम यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से बड़ी संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज गोरखपुर सहित विभिन्न स्टेशनों से पन्द्रह पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

वस्तु और सेवा कर- जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। स्टेशनरी के सामान पर जीएसटी दरों में कटौती से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट...

नई जीएसटी सुधारों के तहत, सरकार ने स्टेशनरी की वस्तुओं पर महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। नए कर ढांचे के तहत, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, अभ्यास पुस्तिकाएँ, ग्राफ़बुक, मानचित्र और चार्ट पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिए गए हैं। इन वस्तुओं पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था। इसी प्रकार इरेजर जो पहले 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आती थी, उसे भी कर मुक्त कर दिया गया है। इन सुधारों ने आवश्यक स्टेशनरी वस्तुओं को और अधिक किफायती बना दिया है, जिससे छात्रों के लिए सीखने की लागत कम हुई है और घरेलू निर्माताओं की मांग बढ़ी है। जीएसटी में कमी से न केवल शिक्षण उपकरण सस्ते हुए हैं, बल्कि देश भर में शिक्षा तक पहुँच भी बढ़ी है। शिवांगमिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

चक्रवाती तूफ़ान मोन्था के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल कई जिलों में बारिश हुयी तो आज भी राज्य के कई हिस्सों में तड़के से ही बादल छाये हुए हैं। इस बीच, तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियन की गिरावट आयी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलने से तापमान में और कमी आ सकती है। अगले चौबीस घंटे में गोरखपुर मण्डल में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जतायी गयी है।
